

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और अन्य

बनाम

इंतेजाम अली जाफरी

13 जुलाई, 2006

[न्यायाधिपति डॉ.ए.आर.लक्ष्मणन और न्यायाधिपति लोकेश्वर सिंह पांटा]

श्रम कानून:

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; धारा 25 (बी), 25 (एफ) और 33 सी (2): आकस्मिक कर्मचारी-छंटनी-श्रम न्यायालय ने एक पुरस्कार पारित किया जिसकी एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा भी पुष्टि की गई। अपील पर, आयोजित किया गया: चूंकि विचाराधीन श्रमिक ने लगभग 4 साल की अवधि में केवल 227 दिनों के लिए काम किया और एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों के लिए नहीं, धारा 25 (एफ) का प्रावधान लागू नहीं होता है। इसलिए, श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को रद्द कर दिया गया-हालांकि, पुरस्कार के बदले में भुगतान, यदि किया जाता है, तो श्रमिक से वसूल नहीं किया जाएगा।

इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा था, वह यह था कि क्या किसी ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरा करने का दावा करता है। लेकिन कथित रूप से

केवल 227 दिनों की सेवा पूरी की और जिनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया, धारा 25 (एफ) के प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम आकर्षित होगा।

अपील की अनुमति दी गई है।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है-

1. श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि श्रमिक ने 240 दिन काम किया है। हालाँकि, श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है। नियोक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष और श्रम न्यायालय के समक्ष भी सामग्री रखी है कि श्रमिक ने लगभग चार वर्षों में केवल 227 दिन काम किया है। चूंकि प्रतिवादी ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों तक काम नहीं किया है, इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी बकाया वेतन आदि के साथ बहाली का आदेश देने में कानून की गलती की है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश भी निरर्थक है। कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि जब प्रारंभिक नियुक्ति ही शून्य हो जाती है।

सिविल क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 6654/2005

(निर्णय एवं आदेश दिनांक 3.6. अपील से।)

श्रम न्यायालय ने माना है कि अपीलकर्ता ने 240 दिन काम किया है।

"दिसंबर, 1987 4 दिन जनवरी, 1988 27 दिन फरवरी, 1988 25 दिन मार्च, 1988 27 दिन मार्च, 1990 23 दिन अप्रैल, 1990 23 दिन मई, 1990 20 दिन जुलाई, 1990 18 दिन अगस्त, 1990 18 दिन, दिसंबर, 1991 14 दिन, जनवरी 1992 24 दिन, फरवरी 1992 4 दिन, 'कुल दिन 227"

प्रत्यर्था ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों तक काम नहीं किया है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। इसके अलावा, कर्मचारी एक कारण गृह सहायक था जिसने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (बी) के प्रावधानों के अनुसार एक कैलेंडर में लगातार 240 दिनों तक काम नहीं किया, एक कैलेंडरवर्ष के अनुसार 240 दिन तक काम होना चाहिए। इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ के प्रावधान तत्काल मामले में इस कारण से आकर्षित नहीं होते हैं कि प्रतिवादी ने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख यानी 28.12.1987 से लगभग 4 साल की अवधि में केवल 227 दिनों के लिए काम किया है, समाप्ति की तारीख 7.2.1992 तक, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और

उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने भी कहा है बकाया वेतन आदि के साथ बहाली का आदेश देने में कानून की गलती की। इसके अलावा, डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश भी गैर-भाषी है।

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि जब प्रारंभिक नियुक्ति ही अमान्य हो जाती है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जबकि प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है- श्रमिक ने भी श्रम न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज नहीं रखे हैं और के श्रम न्यायालय समक्ष रिकॉर्ड भी तलब नहीं किए हैं।

अभिलेखों से पीटीए चलता है कि न तो श्रम न्यायालय ने संबंधित अभिलेखों की मांग की और न ही प्रतिवादी-कर्मचारी ने प्रतिवादी को बुलाने के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया-श्रमिक ने श्रम न्यायालय के समक्ष कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं दिया, श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार रद्द किए जाने और खारिज किए जाने के योग्य है।

उपरोक्त कारणों से, हम निचली अदालतों द्वारा पारित बहाली और बकाया वेतन के आदेश को रद्द करते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि इस न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को कोई भुगतान किया जाता है, तो उसकी वसूली नहीं की जाएगी।

अब पारित आदेश को देखते हुए, धारा 33सी (2) के तहत श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही निष्फल हो गई है।

एसकेएस.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।